Number of brandies of Nationalised Banks in Maharashtra

*170. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what fe the number of branches of nationalised Banks working in Maharashtra at present;

(b) what is the number of branches, out of them, that are working in rural areas; and

(c) what is the number of branches opened and proposed to be opened in the State d.iring 1990-91?

THE FINANCE MINISTER (SHRI YASHWANT SINHA): (a) 4409 branches of Public Sector Banks existed as on 30th June, 1990,

(b) 1792 out of (a) above.

(c) RBI has reported that 53 branches were opened in Maharashtra during the year 1990, and 55 licences are pending as on 26.2.1991 in respect of rural and semi-urban centres in Maharashtra.

खाद्य पदार्थों का निर्यात

*171. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश से भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने रुपए मूल्य के खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया है ;

(ग) चालू वर्ष में खाद्य पदार्थों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी-मुद्रा के प्राप्त होने की संभावना है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य पदार्थों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री, साथ ही में विधि और याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री सुब्रह मण्यम स्वामी): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों (तीय') के दौरान संसाधित खाद्य उत्पादों के निर्यात आंकड़े तथा चालू वर्ष के लिए निर्यात के अनुमानित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(मूल्य लाख रुपए में)

1987–88	29416
1988–89	28963
1989–90	32035
1990–91 (अनुमान)	33500

(घ) जी हां । भारतीय संसाधित खाद्य उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका और ई.ई.सी. जैसे विकसित देशों में कीमत, क्वालिटी और पैकेजिंग क्षेत्रों में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है ।

(ङ) संसाधित खाद्य का निर्यात बढ़ाने के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता, शुल्क वापसी, आयात प्रतिपूर्ति, लाइसेंस, पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर रियायती आयात शुल्क, अग्रिम लाइसेंस आदि जैसे प्रोत्साहन और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजने तथा उनमें भाग लेने के लिए सहायता सरकार द्वारा पहले से ही दी जा रही है ।